द राष्ट्रीय मिल मेजर संघ पेरेल बॉम्बे और अन्य

बनाम

द अपोलो मिल लिमिटेड और अन्य

(एस. के. दास, ए. के. सरकार और वी. एम. हिदायतुल्ला, जे. जे.)

औद्योगिक विवाद-बिजली की कमी के कारण मिलों को बंद करने के लिए मुआवजा-आंशिक रूप से बंद करने का सरकारी आदेश-बिजली की आपूर्ति में कटौती-स्थायी आदेश-बॉम्बे बिजली (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1946 (1946 का बॉम्बे XX), उप-धारा 6A (I) II (I)-बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 (1947 का बॉम्बे XI), उप-धारा 40 (I), 73

1951 में मानसून की विफलता के कारण पनबिजली प्रणाली से बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ और बिजली की खपत को कम करना आवश्यक पाया गया। बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे विद्युत (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 6ए (1) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें विद्युत ऊर्जा के उपयोग को विनियमित किया गया और प्रत्यर्थी-मिलों को काम करने के समय को कम करने के लिए मजबूर किया गया। जिस अवधि के दौरान अल्पकालिक काम जारी रहा, श्रमिकों ने अपने वेतन और महँगाई भत्ते या मुआवजे का दावा किया। जिस औद्योगिक न्यायालय को यह मामला बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 73 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, उसने सभी प्रत्यर्थी मिलों को कर्मचारियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। मिल्स ने दलील दी कि कोई भी मुआवजा देय नहीं था क्योंकि मिल्स को बंद करना बॉम्बे बिजली (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1946 के तहत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में था, और इसलिए, उस अधिनियम की धारा एन (1) ने संदर्भ

को प्रतिबंधित कर दिया, (2) औद्योगिक न्यायालय को मुआवजे के दावे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि मामला स्थायी आदेश 16 और 17 द्वारा कवर किया गया था जो बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 40 (1) के तहत श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच संबंधों का निर्धारक था, और (3) किसी भी मामले में, मुइर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सुती मिल्स मजदूर संघ, कानपुर, [1955] में निर्णय के मद्देनजर कोई मुआवजा देय नहीं था।

अभिनिर्धारित (1) कि बंबई विद्युत (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा ॥ (1) ने केवल विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति में हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पर रोक लगा दी और उन लोगों को संरक्षित किया जिन्होंने उस अधिनियम के तहत पारित आदेशों के अनुसरण में कार्य किया; यह धारा औद्योगिक विवाद को उठाने से नहीं रोकती थी।

(2) कि स्थायी आदेश 16 और 17 में बंद करने की अवधि के लिए केवल नोटिस और मजदूरी के बदले मुआवजे के मामलों पर विचार किया गया था, और बंद करने के लिए मुआवजे के मामलों को शामिल नहीं किया गया था; कि बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 73 के प्रावधान वर्तमान मामले में संदर्भ को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक थे और मुआवजे के दावे को अधिनियम की धारा 40 (1) के साथ पठित स्थायी आदेश 16 और 17 द्वारा वर्जित नहीं किया गया था।

(3) कि मुइर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सूफी मिल्स मजदूर यूनियन, कानपुर में निर्णय केवल बोनस के अवार्ड से संबंधित था और वर्तमान मामले में लागू नहीं था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील सं. 419/1956 1954

अपील (बॉम्बे) संख्या 61 में भारत के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, बॉम्बे के 17 जनवरी, 1955 के निर्णय से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थियों की ओर से एन. सी. चटर्जी, डी. एच. बुच और जे. एन. श्रॉफ।

उत्तरदाताओं के लिए आर. जे. कोलाह, बी. नारायणस्वामी, एस. एन. एंडले, जे. बी. दादाचंजी, रामेश्वर नाथ और पी. एल. वोहरा।

10 मार्च 1960

न्यायालय का निर्णय हिदायतुल्ला, जे. दवारा दिया गया।

यह श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण कहा जाता है) के 17 जनवरी, 1955 के एक निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय की विशेष अनुमति के साथ एक अपील है, जिसके द्वारा उसने बॉम्बे सरकार द्वारा बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 73 के तहत औद्योगिक न्यायालय को भेजे गए मामले में 20 जनवरी, 1954 के औद्योगिक न्यायालय, बॉम्बे के एक निर्णय को उलट दिया था। अपीलकर्ता राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है, जो ग्रेटर बॉम्बे शहर में सूती कपड़ा मिलों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तरदाता अपोलो मिल्स लिमिटेड और अन्य कंपनियाँ हैं जिनके पास विशेष अनुमति याचिका के अनुलग्नक में निर्दिष्ट सूती कपड़ा मिलें हैं और मिल ओनर्स एसोसिएशन, बॉम्बे, जो सूती कपड़ा मिल उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवाद उस मुआवजे से संबंधित है जिसका श्रमिकों ने 1 नवंबर, 1951 और 13 जुलाई, 1952 के बीच की अवधि के दौरान कुछ दिनों में कपड़ा मिलों के कम काम करने या बंद होने के कारण मजदूरी और महँगाई भत्ते के नुकसान के लिए दावा किया था।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः वर्ष 1951 में मानसून विफल हो गया, और टाटा पनबिजली प्रणाली के जलग्रहण क्षेत्र में पानी की कमी हो गई, जिससे मिलों ने अपनी बिजली की आपूर्ति प्राप्त की। इसलिए बिजली की खपत को कम करना आवश्यक पाया गया और सरकार ने विभिन्न मिलों और अपीलकर्ता संघ से परामर्श करने के बाद निर्णय लिया कि 1 नवंबर, 1951 से 30 सप्ताह की अवधि के दौरान मिलों को 48 घंटे के बजाय 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए। यह भी सहमति हुई कि यदि मिलें अपनी बिजली की खपत को अपनी सामान्य खपत के 5/6 वें हिस्से तक कम कर सकती हैं, तो वे पहले की तरह प्रति सप्ताह 48 घंटे काम कर सकती हैं। कुछ मिलों ने अपने स्वयं के जनरेटर स्थापित किए, लेकिन कई अन्य को प्रति दिन 8 घंटे काम करते हुए काम करने के समय को सप्ताह में 40 घंटे तक कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजतन, कुछ मिलों का काम सप्ताह में एक दिन कम हो गया, और मिलों ने अधिकतम 38 दिनों की संख्या खो दी, कुछ अधिक और कुछ कम। एक मिल (रघुवंशी मिल) केवल एक दिन बंद रही। बॉम्बे सरकार का आदेश बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1946 की धारा 6ए (एल) के तहत दिया गया था। जबकि यह छोटा काम जारी रहा, श्रमिकों ने इसके बदले में अपने वेतन और महँगाई भत्ते या मुआवजे का दावा किया। इसके बाद बातचीत हुई, लेकिन जब उनका परिणाम श्रमिकों के लाभ के लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 73 के तहत 30 अक्टूबर, 1952 को बॉम्बे सरकार द्वारा मामले को औद्योगिक न्यायालय को मध्यस्थता के लिए भेजा गया।

मिल्स ने आपत्ति जताई कि मामला स्थायी आदेश 16 और 17 द्वारा कवर किया गया था, और चूंकि मिल्स का आंशिक रूप से बंद बलपूर्वक दुर्घटना के कारण था, इसलिए वे उत्तरदायी नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकार औद्योगिक न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं है, क्योंकि ये स्थायी आदेश बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम,

1946 की धारा 40 (1) के तहत श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच संबंधों का निर्धारण करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बॉम्बे बिजली (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1946 के तहत जारी सरकार के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए और इसलिए कोई मुआवजा देय नहीं है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को उचित मजदूरी मिल रही थी, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मिलों ने कम काम करने के कारण अपने मुनाफे को खो दिया था, अतिरिक्त बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने दिगंबर रामचंद्र बनाम खानदेश मिल्स (1) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि-एक मध्यस्थ जिसे बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1938 की धारा 49ए के तहत आने वाला विवाद भेजा गया था, उसे उस अधिनियम की धारा 26 के तहत बनाए गए स्थायी आदेशों की शर्तों के भीतर विवादों का फैसला करने की अधिकारिता थी, लेकिन उसे स्थायी आदेशों के बाहर के आधार पर नियोक्ताओं के दायित्व का निर्धारण करने की कोई अधिकारिता नहीं थी।

औद्योगिक न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद 20 जनवरी, 1954 को एक निर्णय दिया और सभी प्रतिवादी मिल्स को कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया, यह मानते हुए कि स्थायी आदेश 16 और 17 लागू नहीं थे, और इसलिए, कोई प्रतिबंध नहीं थे। औद्योगिक न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद 20 जनवरी, 1954 को एक निर्णय दिया और सभी प्रतिवादी मिल्स को कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया, यह मानते हुए कि स्थायी आदेश 16 और 17 लागू नहीं थे, और इसलिए, कोई प्रतिबंध नहीं थे। औद्योगिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसूची III, मद 7 के साथ पठित बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की उप-धारा 3,40 (2), 42 (4), 73 और 78 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और पश्चिमी भारत ऑटोमोबाइल एसोसिएशन बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण,

बॉम्बे (1) में संघीय न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उसे मुआवजा देने का अधिकार क्षेत्र था। इसलिए, औद्योगिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर श्रमिक मुआवजे के हकदार हैं, जिसका मूल्यांकन श्रमिकों को मिलने वाले मजदूरी और महँगाई भत्तों के 50 प्रतिशत की दर से किया जाता है, यदि मिलें बंद रहने के दिनों में काम करतीं।

उस अवार्ड के खिलाफ, मिल मालिक संघ और दो मिल्स ने अपीलीय न्यायाधिकरण, बॉम्बे में अपील की। औद्योगिक न्यायालय के समक्ष उठाई गई सभी दलीलों को एक बार फिर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया। दो नए विवाद उठाए गए, अर्थात्, मुआवजे के दावे को बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1946 की धारा 11 के तहत वर्जित किया गया था, और मुइर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सुती मिल्स मजदूर यूनियन, कानपुर (2) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा भी वर्जित किया गया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने अब हमारे समक्ष विवादित अपने निर्णय द्वारा, अपील को अनुमति दी और औद्योगिक न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया, और कर्मचारियों के दावे को खारिज कर दिया। इसने अभिनिर्धारित किया कि भले ही स्थायी आदेश 16 और 17 मामले को शामिल करते हैं, दिगंबर रामचंद्र के मामले (1) में निर्णय अब धारा 40 (2) के प्रावधानों और अनुसूची III को जोड़ने के कारण लागू नहीं किया जा सकता है और बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम में अनुसूची III, मद 7 को जोड़ा गया, जिसके प्रावधानों को बॉम्बे में जगह नहीं मिली। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1938, जिसके तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय दिया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहले उद्धृत संघीय न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रमिकों को उनके वेतन और महँगाई भत्ते के आधे के बराबर मुआवजे का अवार्ड

उचित और न्यायसंगत था। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने मुइर मिल्स मामले (1) में इस न्यायालय के फैसले से श्रमिकों के दावे को अस्वीकार करने के लिए मजबूर महसूस किया और अपील को स्वीकार कर लिया। मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय नहीं लिया कि क्या बॉम्बे बिजली (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 11 मुआवजे के अनुदान पर रोक लगाती है।

इस मामले में अपीलार्थी ने पहले तर्क दिया कि मुइर मिल्स मामला (1) लागू नहीं हुआ, और आगे कहा कि यदि वह मामला रास्ते से बाहर था, तो अपीलीय न्यायाधिकरण के अन्य निष्कर्षों और औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1950 की धारा 7 को देखते हुए, अपील विफल होनी चाहिए थी, क्योंकि कानून का कोई सवाल नहीं बचा था और अपीलीय न्यायाधिकरण निर्णय को उलटने में अक्षम था। दूसरी ओर, मिल मालिक संघ ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण की राय कि मुइर मिल्स मामला (1) लागू किया गया था, सही थी, कि बॉम्बे बिजली (विशेष शक्तियां) अधिनियम की धारा 11 ने इन कार्यवाही को प्रतिबंधित कर दिया था, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंद बल प्रयोग के कारण हुआ था जिसके लिए मिल्स जिम्मेदार नहीं थे, स्थायी आदेश 16 और 17 पक्षों के बीच संबंधों का निर्धारण करने वाले थे और मुआवजे का दावा स्वीकार्य नहीं था। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उठाई गई अन्य आपत्तियों को हमारे समक्ष नहीं दबाया गया।

हम सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं कि क्या बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1946 की धारा 11 संदर्भ को प्रतिबंधित करती है। वह धारा इस प्रकार हैः

"11 (1) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही किसी भी ऐसी चीज के लिए नहीं होगी जो धारा 3,4,5,6,6 ए, 6 बी या 6 सी

के तहत किए गए या किए गए किसी आदेश, निर्देश या आवश्यकता के अनुसरण में सद्भावना से की गई हो या करने का इरादा हो।"

बॉम्बे सरकार द्वारा इस मामले में जो आदेश दिया गया था, वह धारा 6ए की उप-धारा (1) के तहत था, जिसमें कहा गया हैः

"6ए (एल) उस समय लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, या धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत दी गई किसी अनुमति या किसी कानून के आधार पर प्रभावी किसी उपकरण के बावजूद, प्रांतीय सरकार विद्युत ऊर्जा के वितरण, आपूर्ति, खपत या उपयोग को नियंत्रित करने की दृष्टि से एक आदेश दे सकती है-

(ए) ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह आदेश में निर्दिष्ट कर सकती है, एक लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा का वितरण या आपूर्ति या ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए एक उपभोक्ता द्वारा ऐसी ऊर्जा का उपयोग;

(बी) प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करने के लिए जिसमें, या अवधि या अवधियों के दौरान विद्युत उर्जा की आपूर्ति के लिए लाईसेंसी द्वारा वचन पत्र के माध्यम से कार्य किया जाना है।"

प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि ऊपर उद्धृत धारा 11 की उप-धारा (1) मध्यस्थता के उपाय को बाधित करती है, क्योंकि मिलों को बंद करना सद्भावना से था, और धारा 6ए (एल) के तहत दिए गए निर्देश या आदेश के अनुसरण में था श्री कोलाह ने बॉम्बे बिजली (विशेष शक्तियां) अधिनियम की योजना और विशेष रूप से दंड और अपराधों से निपटने वाली धाराओं का उल्लेख किया और तर्क दिया कि मिल असहाय थे और कुछ समय के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने दावा

किया कि धारा 11 (1) का संरक्षण उनके लिए उपलब्ध था, और तर्क दिया कि यह किसी भी प्रकार की कार्रवाई से प्रतिरक्षा देता है।

वर्तमान कार्यवाही उस अवधि के मुआवजे के लिए है जिसके दौरान मिलें बंद रहीं। यह दावा श्रमिकों द्वारा मिलों के खिलाफ किया जाता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला खंड विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और इसकी खपत में हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को रोकता है। यह उपभोक्ता और इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा के आपूर्तिकर्ता के लिए एक सुरक्षा है, और उन लोगों की भी रक्षा करता है जो आदेश को लागू करने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ बिजली कम होने या कुछ समय के लिए मिलों के बंद होने की भी कोई शिकायत नहीं है। न तो मिलों ने और न ही श्रमिकों ने ऐसा कोई विवाद उठाया है। इसके अलावा, उप-धारा एक संरक्षण खंड है जिसे आमतौर पर एक अधिनियम में पेश किया जाता है, जहां यह नई या असामान्य शक्तियां देता है, और इसे इसके तहत कार्य करने या लागू करने वाले व्यक्तियों को प्रतिरक्षा देने के लिए बनाया गया है। संरक्षण का दायरा इसकी आपूर्ति और खपत के संबंध में है। बिजली जो अकेले अधिनियम की धारा 6ए (एल) के तहत जारी आदेश द्वारा कम की जाती है। इसलिए, धारा 11 की पहली उप-धारा द्वारा प्रदत्त संरक्षण एक औद्योगिक विवाद को उठाने से नहीं रोकता है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान के न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक अवार्ड होता है जो आदेश के पालन द्वारा नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यह तर्क कि औद्योगिक न्यायालय के पास संदर्भ की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि राज्य सरकार इसे नहीं बना सकती थी, प्रत्यर्थियों द्वारा दबाव नहीं डाला गया था और इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे एक अन्य रूप में उठाया गया था, जैसा कि अगली कड़ी में दिखाई देगा। हालाँकि, दोनों पक्षों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश की आलोचना की, उत्तरदाताओं ने उनके प्रतिकूल निष्कर्षों को चुनौती दी। अब अपीलार्थी के इन मामले से निपटना

आवश्यक है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को औद्योगिक न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि उसके समक्ष अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था और यह औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1950 की संस्था 7 (1) (बी) में उल्लिखित आठ मामलों में से किसी के भीतर नहीं आता था, जिसने अपीलार्थी को अपीलीय अधिकार क्षेत्र दिया था, जिन मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन मामलों का उन कारणों से विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है जिनके बारे में हम आगे बताते हैं।

अपीलार्थी का मामला यह था कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास औद्योगिक न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि उसके समक्ष प्रस्तुत अपील में कानून का कोई सारवान प्रश्न नहीं था और न ही यह मामला आठ गणना किए गए विषयों के भीतर आता था, जो औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1950 की धारा 7 (एल) (बी) में बताये गए है और जो अपीलीय न्यायाधिकरण को क्षेत्राधिकार प्रदान करते है। अपीलार्थी ने जो मामले संदर्भित किये है, उनमें यह बताया गया है कि अपीलीय प्राधिकरण तथ्यों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन मामलों के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक विवाद (अपीलीय प्राधिकरण) अधिनियम अपील प्राधिकरण की अपीलीय शक्तियों को बताता है जो कि यह है कि यदि कोई मामले में विधि का सारवान प्रश्न उत्पन्न होता है या मामला इसमें बताये गए आठ विषयों से संबंधित है। उत्तरदाताओं ने मामले को धारा 7 (एल) (बी) के खंड (i) के भीतर लाने का प्रयास किया, अर्थात "मजदूरी", जो आठ विषयों में से एक है। लेकिन यहाँ मुआवजे के अलावा मजदूरी का कोई सवाल ही नहीं है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया

कि साक्ष्य को समायोजित किए बिना तैयार किए गए निष्कर्ष में कानून का प्रश्न और सिद्ध तथ्यों से कानूनी निष्कर्ष और इस प्रकार एक अपील शामिल है। उन्होंने एंग्लो-ईरानी तेल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम पेट्रोलियम श्रमिक संघ (1) और क्रॉम्पटन पार्किंसन (वर्क्स) बनाम इसके कामगार (2) पर भरोसा किया। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि भले ही विषय-वस्तु आठ गणना किए गए विषयों में से किसी के भीतर नहीं आता था, लेकिन इसमें शामिल कानून का एक बड़ा सवाल था, क्योंकि यह तय करना आवश्यक था कि बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम और स्थायी आदेशों के प्रावधानों को देखते हुए मुआवजे का दावा स्वीकार्य नहीं था या नहीं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि श्रमिकों को नियुक्त करना जारी रखने में विफलता विद्युत ऊर्जा की कम आपूर्ति के कारण थी, और सवाल यह है कि क्या इन स्वीकृत परिस्थितियों में, बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 40 (1) और अनुसूची । की वस्तु 9 के साथ पठित स्थायी आदेश 16 और 17 ने नियोक्ताओं को मजदूरी और महँगाई भत्ते के नुकसान के मुआवजे के दावे से मुक्त कर दिया। प्रत्यर्थियों ने दावा किया कि उन्होंने किया, जबकि अपीलार्थी ने कहा कि उन्होंने नहीं किया, और उसी अधिनियम का ।।। उप-धारा 40,(2), 42 (4), 73 और 78 (एल) (ए) और एस. एच. की मद 7 का उल्लेख किया। यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार अपील सक्षम थी।

इस मामले का सार स्थायी आदेश 16 और 17 के प्रावधान हैं, जिन्हें बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 40 (1) के साथ पढ़ा जाना है। स्थायी आदेश 16 और 17 इस प्रकार हैंः-

"16. कंपनी, किसी भी समय या समय, आग लगने, आपदा, बिजली आपूर्ति बंद होने की स्थिति में, महामारी, नागरिक हंगामा या अन्य कारणों से, कंपनी के नियंत्रण से

परे, किसी भी मशीन या मशीनों या विभाग या विभागो को किसी भी अवधि या अवधियों के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से, बिना किसी सूचना के और बिना किसी मुआवजे के रोक सकती है। कार्य घंटों के दौरान इस आदेश के तहत किसी भी मशीन या विभाग के बंद होने की स्थिति में, प्रभावित कार्यकर्ताओं को संबंधित विभाग में और समय-रक्षक के कार्यालय में नोटिस बोर्डों पर लगाए गए नोटिसों द्वारा सूचित किया जाएगा, जितनी जल्दी हो सके, जब काम फिर से शुरू किया जाएगा और क्या उन्हें मिल में रहना है या छोड़ना है। मिल के ठहराव की अवधि आम तौर पर ठहराव शुरू होने के एक घंटे से अधिक नहीं होगी। यदि निरोध की अवधि एक घंटे से अधिक नहीं है, तो इस तरह से मज़दूरी पर लिए गए कार्यकर्ताओं को निरोध की अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि मिल में निरोध की अवधि एक घंटे से अधिक है, तो इस तरह से मज़दूरी पर लिए गए कार्यकर्ता उस पूरे समय के लिए मजदूरी प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसके दौरान उन्हें बंद होने के परिणामस्वरूप मिल में मज़दूरी पर रखा जाता है। कारीगरों के मामले में, पिछले महीने की औसत दैनिक आय को दैनिक मजदूरी माना जाएगा।

17. आदेश 16 के तहत किसी भी ऑपरेटिव प्ले-ऑफ को सेवा से बर्खास्त नहीं माना जाएगा, बल्कि अस्थायी रूप से बेरोजगार माना जाएगा, और आदेश 16 में उल्लिखित सीमा को छोड़कर ऐसी बेरोजगारी के दौरान मजदूरी का हकदार नहीं होगा। जब भी व्यवहार्य हो, सामान्य काम को फिर से शुरू करने और आदेश 16 के तहत बंद किए गए सभी कार्यकर्ताओं के बारे में एक उचित सूचना दी जाएगी, जो काम के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं, जब सामान्य काम फिर से शुरू किया जाता है; उन्हें बहाली का पूर्व अधिकार होगा।"

प्रत्यर्थियों का तर्क दो प्रकार का थाः (1) इन दो स्थायी आदेशों में पूरी तरह से बिजली बंद होने के कारण बंद करने को शामिल किया गया था, और (2) बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 40 (1) के तहत, स्थायी आदेश अनुसूची । में निर्दिष्ट सभी औद्योगिक मामलों के संबंध में नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंधों का निर्धारक थे, जिसमें निम्नलिखित आइटम शामिल हैंः-

"4. किसी विभाग या विभाग के किसी खंड या पूरे उपक्रम को बंद करना या फिर से खोलना।

9. अस्थायी रूप से काम बंद करना जिसमें नौकरी छोड़ना और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकार और देनदारियाँ शामिल हैं।"

उन्होंने दिगंबर रामचंद्र के मामले (1) में भी निर्णय का आह्वान किया और कहा कि बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 40 में दूसरी उप-धारा को जोड़कर भी स्थिति में बदलाव नहीं किया गया था।

हम इस स्तर पर धारा 40 पढ़ सकते हैंः

"40. (1) इस अध्याय के अधीन और प्रवर्तन में किसी नियोक्ता और उसके कर्मचारियों के संबंध में स्थायी आदेश, या जहां ऐसे कोई स्थायी आदेश नहीं हैं, धारा 35 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के तहत लागू होने वाले आदर्श स्थायी आदेश, यदि कोई हों, अनुसूची । में निर्दिष्ट सभी औद्योगिक मामलों के संबंध में नियोक्ता और उसके कर्मचारियों के बीच संबंधों का निर्धारक होंगे।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार, किसी कार्मिक या प्रतिनिधि संघ के मामले को जो धारा 78 के पैरेग्राफ ए के खंड ए की प्रकृति का हो, उसे श्रम न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है।"

प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि केवल पहली उप-धारा लागू होती है, और ऊपर उद्धृत स्थायी आदेश 16 और 17 के तहत, कोई मुआवजे का दावा नहीं किया जाता है। अपीलार्थी ने इंगित किया कि दूसरी उप-धारा ने पहली उप-धारा को बाहर कर दिया, क्योंकि गैर-अबाधित खंड जिसके साथ इसे प्रस्तुत किया गया है और श्रम न्यायालय के पुरस्कारों से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में औद्योगिक न्यायालय की स्थिति को देखते हुए, पहली भी पहली उप-धारा या स्थायी आदेशों से बाध्य नहीं थी। अपीलार्थी के विवाद में कुछ बल है, लेकिन, हमारी राय में, स्थायी आदेश 16 और 17, संदर्भ में, मुआवजे के दावे पर लागू नहीं होते हैं जैसा कि यहाँ किया गया है। स्थायी आदेश 16 "बिना किसी सूचना के और नोटिस के बदले मुआवजे के बिना" रोक लगाने की बात करता है। इस मामले में श्रमिकों द्वारा जो मुआवजे का दावा किया जाता है, वह नोटिस के बदले में नहीं है, यानी उस अवधि के लिए जिसके संबंध में नोटिस दिया जाना था। वह अवधि बंद होने की तारीख से पहले की होगी। स्थायी आदेश उन मामलों पर विचार करता है जिनमें एक नोटिस दिया जाना है और फिर नोटिस के बदले में कोई मुआवजा देय नहीं है। हालाँकि, यहाँ एक अलग प्रकार का प्रश्न है, और यह स्थायी आदेश 16 द्वारा कवर नहीं किया गया है, भले ही बंद करने का कारण सत्ता का बंद होना था। स्थायी आदेश 17 "मजदूरी" की बात करता है, और हम यहाँ मजदूरी से नहीं बल्कि मुआवजे से संबंधित हैं जो मजदूरी के समान नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, स्थायी आदेश 16 और 17 को वर्तमान तथ्यों को शामिल करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए वे पक्षों के बीच संबंधों के निर्धारक नहीं हैं।

वर्तमान विवाद को बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 73 (2) के तहत औद्योगिक न्यायालय को भेजा गया था। उस धारा में कहा गया हैः

"इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार, किसी भी समय, औद्योगिक न्यायालय के मध्यस्थता के लिए एक औद्योगिक विवाद को संदर्भित कर सकती है, यदि श्रम अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर या अन्यथा यह संतुष्ट हो जाता है कि .....

(2) विवाद के अन्य तरीकों से निपटारे की संभावना नहीं है;"

गैर-अस्थाई खंड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम के अन्य प्रावधानों के बावजूद, एक औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को भेजा जा सकता है। उस अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक विवाद का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ किसी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई विवाद या अंतर है, जो किसी औद्योगिक मामले से जुड़ा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के गैर-रोजगार से संबंधित सभी मामले शामिल हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन श्रमिकों को कुछ दिनों में नियुक्त नहीं किया गया था, और इस प्रकार, गैर-रोजगार की अवधि के लिए मुआवजे के उनके दावे के बारे में एक औद्योगिक विवाद था। सूची प्रथम की मद संख्या 9, में अस्थायी बंद के संबंध में स्थायी आदेश तैयार करने की शक्ति दी। स्थायी आदेशों में केवल बंद करने की अवधि के लिए नोटिस और मजदूरी के बदले में मुआवजे को शामिल किया गया था, लेकिन बंद करने के लिए मुआवजे को नहीं। स्थायी आदेशों के बारे में हमने जो विचार लिया है, उसमें यह तय करना आवश्यक नहीं है कि सूची III की मद 7 है या नहीं। केवल स्थायी रूप से बंद करने के लिए मुआवजे से संबंधित है, या क्या सूची की मद 9 है। मैंने अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मुआवजे से संबंधित एक स्थायी आदेश देने की शक्ति दी। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि स्थायी आदेश 16 और 17, जैसा कि वे खड़े हैं, बंद करने के लिए मुआवजे के मामले को शामिल नहीं करते हैं।

बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 73 के तहत औद्योगिक न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, क्योंकि राज्य सरकार अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक औद्योगिक विवाद को उसके पास भेज सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए औद्योगिक न्यायालय की अधिकारिता पर आपत्ति नहीं उठाई गई थी। लेकिन तर्क को एक अन्य रूप में यह दिखाने के लिए आगे बढ़ाया गया कि स्थायी आदेश 16 और 17 निर्धारक थे और औद्योगिक न्यायालय को उन स्थायी आदेशों के अनुसार के अलावा किसी भी तरह से निर्णय लेने में सक्षम नहीं बनाते थे। दिगंबर रामचंद्र के मामले (1) पर भी भरोसा किया गया था, जहां चागला, सी. जे. और भगवती, जे. ने फैसला किया कि मध्यस्थ स्थायी आदेशों से बंधा हुआ है और उनसे बाहर नहीं जा सकता है। हमारी राय है कि स्थायी आदेश 16 और 17 पहले से बताए गए कारणों से वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं, और हम उस निर्णय से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं जहां तक यह माना गया है कि स्थायी आदेशों में बंद करने के लिए मुआवजे का मामला भी शामिल है। हम आगे ध्यान देते हैं कि बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1938 में बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की अनुसूची III के समान कोई वस्तु नहीं थी। बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में, अहमदाबाद बनाम अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद (2), सर एच. वी. दिवतिया, राजाध्यक्ष, जे. और श्री डी. वी. व्यास (बाद में, व्यास, जे.) में सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया कि स्थायी आदेशों में आय के नुकसान के मुआवजे का मामला शामिल नहीं है। मुख्य टिप्पणी निर्णय को पर्याप्त रूप से सारांशित करती है, और इसे उद्धृत किया जा सकता है। इसमें लिखा हैः

"हालांकि श्रमिक काम बंद होने की अवधि के दौरान अपने वेतन की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि यह मामला स्थायी आदेशों में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें अपनी आय के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने वाले परिवर्तन की कोई सूचना देने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि

न्यायालय की अधिकारिता स्थायी आदेश संख्या 16 और 17 के प्रावधानों द्वारा बाधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ का संदर्भ बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1938 की धारा 43 के तहत था; लेकिन बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 73 के प्रावधान उसी विषय पर एक संदर्भ को शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए, हमारी राय है कि मुआवजे के दावे को बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 40 (1) के साथ पठित स्थायी आदेश 16 और 17 द्वारा बाधित नहीं किया गया था।"

प्रत्यर्थियों ने आगे तर्क दिया कि औद्योगिक न्यायालय द्वारा लागू और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया सामाजिक न्याय का सिद्धांत मुइर मिल्स मामले (1) में इस न्यायालय के फैसले के कारण लागू नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बोनस के मामले का निर्णय वर्तमान मामले के साथ किया गया था और 38 मिलों के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बोनस और महँगाई भत्ते दोनों में वृद्धि की गई थी और यहां तक कि शेष 15 मिलों, जिन्हें नुकसान हुआ था, ने अपने श्रमिकों को न्यूनतम बोनस दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि मजदूरी उचित थी और बोनस दिया गया था और महँगाई भत्ता बढ़ाया गया था, और अपीलीय न्यायाधिकरण ने इनकार करने में इस सब को ध्यान में रखते हुए कहा कि कम काम करने के कारण मिलों को भारी नुकसान हुआ, और उन दिनों के लिए मजदूरी या मुआवजे का भुगतान करना सरासर अन्याय था जब मिल बंद रहे और सामान्य काम बंद होने के कारण अपना लाभ खो दिया।

मुइर मिल्स मामला (1) बोनस के अवार्ड से संबंधित था, जो लाभ से जुड़ा हुआ है। यह निर्धारित किया गया था कि चूंकि एक औद्योगिक उपक्रम में नियोजित श्रम हमेशा बदल रहा है, बोनस का अवार्ड केवल उस लाभ से हो सकता है जिसमें किसी विशेष वर्ष में श्रम ने योगदान दिया है और श्रम यह दावा नहीं कर सकता है कि कुछ अन्य वर्षों के लाभ और भंडार का उपयोग उन्हें बोनस देने के उद्देश्य से किया जाना

चाहिए। हम इस मामले में बोनस के अवार्ड से संबंधित नहीं हैं, और इसलिए हमें उन कारणों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने उस मामले में इस न्यायालय में अपील की थी। जिस संकीर्ण क्षेत्र में सामाजिक न्याय की मांग है कि जबरन बेरोजगारी में जाने वाले श्रमिकों को मुआवजा मिलना चाहिए, वह काफी अलग है। सामाजिक न्याय संविदात्मक संबंधों पर आधारित नहीं है और सेवा अनुबंध के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। यह इन सिद्धांतों के बाहर कुछ है, और इसका समर्थन करने के लिए अनुबंध के बिना न्याय करने के लिए आह्वान किया जाता है। महाजन, जे. (उस समय के रूप में) ने वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, बॉम्बे (9) में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"हमारी राय में, न्यायनिर्णयन का अर्थ स्वामी और सेवक के सख्त कानून के अनुसार न्यायनिर्णयन नहीं है। न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय में किसी विवाद के निपटारे के लिए प्रावधान हो सकते हैं जो कोई भी न्यायालय आदेश नहीं दे सकता है यदि वह सामान्य कानून से बाध्य था, लेकिन न्यायाधिकरण इन सीमाओं से किसी भी तरह से बंधा हुआ नहीं है। लुडविग टेलर द्वारा श्रम विवाद और सामूहिक सौदेबाजी के खंड । में, पृष्ठ 536 में कहा गया है कि औद्योगिक मध्यस्थता में मौजूदा समझौते का विस्तार या एक नया समझौता करना शामिल हो सकता है, या सामान्य रूप से एक नए दायित्व का निर्माण या पुराने में संशोधन, जबकि वाणिज्यिक मध्यस्थता आम तौर पर मौजूदा दायित्वों और मौजूदा समझौतों से संबंधित विवादों की व्याख्या से संबंधित होती है। हमारी राय में, यह श्रम विवादों में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के कार्यों के बारे में एक सच्चा बयान है।"

यहाँ, औद्योगिक न्यायालय (जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है) द्वारा नुकसान को दो भागों में विभाजित करने से बेहतर उपाय क्या हो सकता

था, एक औद्योगिक संस्थाओं द्वारा और दूसरा श्रमिकों द्वारा वहन किया जाना था? एक या दूसरे पक्ष द्वारा सुझाया गया कोई अन्य आधार नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि श्रम को नुकसान बोनस के अनुदान के विचार में गया था, और दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की गई थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसा कहता है, लेकिन बोनस लाभ से बाहर आना है और यह उस लाभ में श्रम का हिस्सा है जो उसने अर्जित करने में मदद की है, ताकि मजदूरी और जीवित मजदूरी के बीच की खाई को कम किया जा सके। वर्तमान संदर्भ में क्षतिपूर्ति मजदूरी और महँगाई भत्ते के नुकसान के लिए है, और दोनों को किसी भी सिद्धांत पर एक साथ नहीं माना जा सकता है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने लिए जो सूत्र विकसित किया था, उसके बावजूद उसने कुछ अन्य कारकों को ध्यान में रखा जो उक्त सूत्र से काफी अलग थे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का वास्तव में यह कहने का मतलब था कि श्रमिकों को बोनस का भुगतान किया गया था, इसलिए उन्हें कुछ दिनों में मजदूरी खोने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुआवजे का भुगतान किया जाता तो बोनस को कम करना पड़ता। यदि यही अर्थ है, जैसा कि स्पष्ट है, तो मुआवजे का सवाल बिल्कुल भी तय नहीं किया गया था। हमारी राय में, यह तर्क बिंदु से परे था। यह पूरी तरह से मायने नहीं रखता था कि क्या वर्ष में लाभ किया गया था या नुकसान हुआ था, यदि नियोक्ता श्रम बल को बनाए रखना जारी रखते थे ताकि उन दिनों के लिए उपलब्ध रहे जिन दिनों में मिलें काम करती थीं।

हमारी राय में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष देने के बाद कि मजदूरी और महँगाई भत्तों के आधे के बराबर मुआवजे का दावा न्यायसंगत और उचित था, यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि यह मुइर मिल्स मामले (1) में इस न्यायालय के निर्णय के कारण स्वीकार्य नहीं था। उस मामले का यहाँ तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार करने में भी

गलती की कि चूंकि बोनस दिया गया था, इसलिए मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया जा सका। ऐसा प्रतीत होता है कि बादली श्रमिकों का मामला अलग से नहीं उठाया गया है, और हम उन्हें मुआवजा नहीं देने का कोई कारण नहीं देखते हैं। लेकिन इस तरह के मुआवजे का भुगतान उसी शर्त के अधीन होगा, जो औद्योगिक न्यायालय द्वारा लगाई गई थी।

परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाएगी, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया जाएगा और औद्योगिक न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया जाएगा। उत्तरदाता यहाँ और नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों में लागत वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।